RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 22 APRIL TO 28 APRIL 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 35 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

तालों में बंद तेल का किसको फायदा? ONGC, OIL इंडिया को महंगा पड़ रहा सस्ता क्रूड Page 2

कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को 'अप्रत्याशित' झटका, Page 5

Mahindra KUV100 NXT का बीएस6 मॉडल लॉन्च, कीमत 5.54 लाख से शुरू Page 7

editoria!

तेल: रसातल में भाव

कोरोना संकट की गहरी मार कच्चे तेल के वैश्विक बाजार पर भी पड़ी है। वायदा बाजार में सोमवार को इसकी कीमतें इतिहास में पहली बार शून्य से भी नीचे पहुंच गईं। अमेरिकी वायदा बाजार में कच्चा तेल लुढ़कते हुए नेगेटिव में चला गया, शून्य से 36 डॉलर नीचे। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) का वायदा भाव मई डिलीवरी के लिए -37.63 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमत माइनस में जाने का यह मतलब नहीं है कि आज या कल से तेल खरीदने पर इसे बेचने वाला आपको साथ में कुछ पैसे भी देगा। दरअसल मई महीने में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए जो ठेके दिए जाते हैं वे अब नेगेटिव में चले गए हैं। तेल उत्पादक देश दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदने को कह रहे हैं, लेकिन वैश्विक लॉकडाउन के कारण कोई भी देश तेल नहीं खरीद रहा, इसलिए कीमत इतनी गिर गई। हालत यहां तक पहुंच गई है कि तेल उत्पादक देश अब खरीदारों को पैसे देकर तेल खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तेल नहीं बिका तो उनके सामने स्टोरेज की समस्या खड़ी हो जाएगी। असल में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन है। लोग घरों में बंद हैं। गाड़ियां नहीं चल रहीं, विमान नहीं उड़ रहे, कारखानों में भी उत्पादन ठप है। इसके कारण क्रूड की मांग में भारी गिरावट आई है। सऊदी अरब और रूस के बीच चले प्राइस वॉर ने पहले ही तेल का अपच कर रखा था। अब तेल उत्पादक देशों के सामने तेल रखने की विकराल समस्या खड़ी हो रही है, जिसे देखते हुए कई तेल फर्में विशाल टैंकर शिप किराये पर ले रही हैं ताकि अतिरिक्त स्टॉक उनमें रखा जा सके। अमेरिका के लिए यह सिरदर्द सबसे बड़ा है क्योंकि उसकी शेल ऑयल कंपनियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वे इन हालात से कैसे निपटें। ऐसी कई कंपनियां अगले कुछ महीनों में दिवालिया हो सकती हैं, जिससे वहां बेरोजगारी का संकट भी गहराएगा। कच्चे तेल की कीमतों के रसातल में पहुंचने का भारत पर भी बुरा असर पड़ेगा। दरअसल इसके चलते कई खाड़ी देशों की इकोनॉमी डावांडोल हो सकती है क्योंकि उनका ज्यादातर जीडीपी तेल से ही आता है। इन देशों में करीब 80 लाख भारतीय काम करते हैं जो हर साल करीब 50 अरब डॉलर की रकम भारत भेजते हैं। खाड़ी की इकोनॉमी के गड़बड़ होने का मतलब है, इनमें से अधिकतर का बेरोजगार हो जाना। इसके अलावा भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है, जिस पर जबर्दस्त आफत आने वाली है। संकट से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक नई मुश्किल होगी लेकिन अभी इस बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। हमें धैर्यपूर्वक स्थितियों के संभलने का इंतजार करना होगा और खाड़ी देशों से अपना संवाद बनाए रखना होगा।

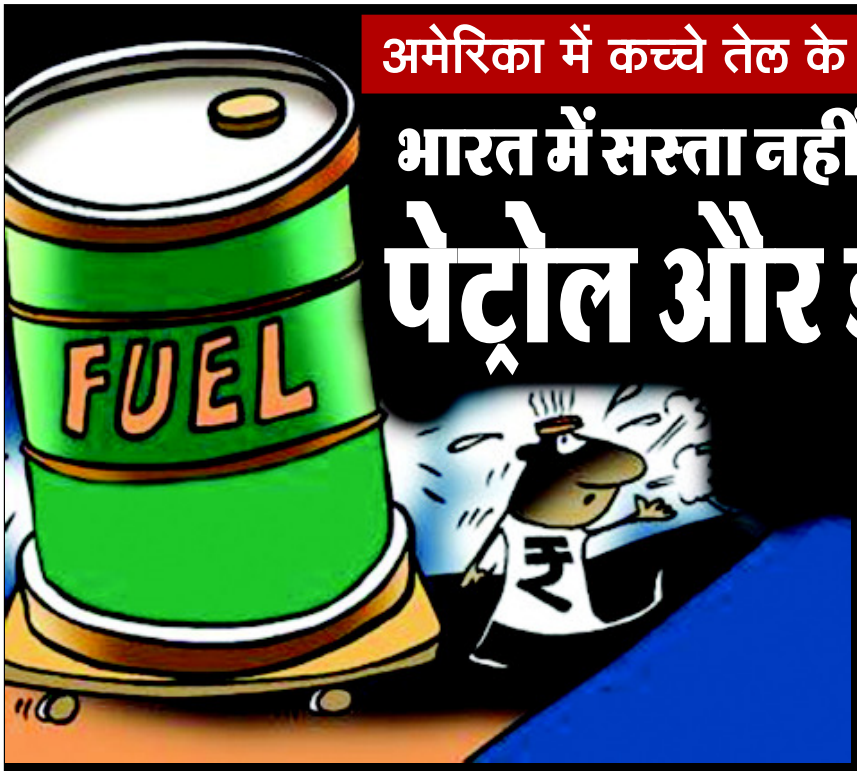

अमेरिका में कच्चे तेल के दाम गिरे पर

भारत में सस्ता नहीं बिकेगा पेट्रोल और डीजल

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका के कच्चे तेल बाजार में आए 'जलजले' से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ी कटौती नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि भारत में ईंधन के घरेलू दाम अलग 'बेंचमार्क' से तय होते हैं और रिफाइनरियों के पास पहले से कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और वे अभी अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद नहीं कर रही हैं। अमेरिकी बाजार में मची उथलपुथल के बीच कच्चे तेल के दाम इस कदर गिरे कि तेल खरीदार उसे उठाने को तैयार नहीं हैं और बेचने वाले को फिलहाल उसे अपने भंडार गृह में रखने को कह रहे हैं। हो सकता है इसके लिये उन्हें भुगतान भी करना पड़े। कच्चे तेल का उत्पादन और इसकी उपलब्धता जरूरत से ज्यादा होने के बीच कोरोना वायरस की वजह से मांग घटने के चलते कारोबारी अपने अवांछित स्टॉक को जल्द से जल्द निकालना चाह रहे हैं। इससे मई डिलिवरी के अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल के दाम 'ढह' गए।

बुक ऑर्डर की डिलिवरी नहीं ले पा रहे कारोबारी

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन संजीव सिंह ने बताया कि कारोबारी पहले से बुक किए गए ऑर्डर की डिलिवरी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि मांग नहीं है। इस वजह से अमेरिका में कच्चे तेल के दाम नीचे आए हैं। वे तेल को विक्रेता की तरफ से उसके भंडार में रखने के लिए उल्टा उसे भुगतान कर रहे हैं। सिंह ने कहा, 'यदि आप जून के वायदा को देखें तो यह सकारात्मक रुख में करीब 20 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।'' उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के निचले दाम लघु अवधि के लिए तो अच्छे हैं, पर दीर्घावधि में यह तेल आधारित अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उत्पादकों के पास खोज और उत्पादन के लिए निवेश करने को अधिशेष नहीं होगा। इससे अंततः उत्पादन घटेगा। हालांकि, उन्होंने ईंधन के खुदरा दामों पर कोई टिप्पणी नहीं की, जो 16 मार्च से स्थिर हैं।

दिल्ली में पेट्रोल 69.59 और डीजल 62.29 प्रति लीटर

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोलियम कंपनियों ने ईंधन दामों में कटौती नहीं की है। पहले उन्होंने इसे तीन रुपये प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी और एक अप्रैल से बेचे जा रहे स्वच्छ भारत चरण-छह ईंधन पर लागत में करीब एक रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ समायोजित किया। दिल्ली में पेट्रोल 69.59 रुपये और डीजल 62.29 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इस बीच, इंडियन आयल कॉरपोरेशन ने बयान में कहा कि अमेरिका में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) तेल भारी गिरावट के साथ शून्य से नीचे 37.63 डॉलर प्रति बैरल पर बोला गया। इसकी वजह अंतिम तारीख से एक दिन पहले 20 मई के आपूर्ति अनुबंध की घबराहटपूर्ण बिकवाली है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कोविड-19 की वजह से मांग में आई भारी गिरावट के बीच उन्हें डिलिवरी लेनी होती। भंडारण की परेशानी है। बयान में कहा गया है कि 20 जून का डब्ल्यूटीआई वायदा और 20 मई का आईसीई ब्रेंट अब भी 16 डॉलर प्रति बैरल और 21 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे हैं।

भारत में दाम का निर्धारण अलग बेंचमार्क से

एनर्जी एंड एन्वायर्नेंट स्टडीज, गेटवे हाउस के फेलो अमित भंडारी ने कहा, 'नकारात्मक कीमतों का भारत में ईंधन कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। भारत में दाम अलग बेंचमार्क से निर्धारित होते हैं जो इस समय 25 डॉलर प्रति बैरल है। ऐसे में भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों में कमी नहीं आएगी। भारत में रिफाइनरियों के पास पहले से ही जरूरत से अधिक भंडार है। राष्ट्रव्यापी बंद की वजह से ईंधन की मांग में भारी गिरावट आई है। ऐसे में वे अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद नहीं कर सकतीं। रिफाइनरियों ने पहले ही अपना परिचालन आधा कर दिया है क्योंकि वे पहले उत्पादित ईंधन को ही नहीं बेच पाई हैं। भंडारी ने कहा कि भारत प्रतिदिन 40 लाख बैरल कच्चे तेल (1.4 अरब बैरल सालाना) का आयात करता है। पिछले पांच साल के दौरान कच्चे तेल के दाम 110 डॉलर प्रति बैरल से पिछले साल 50-60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए। भारत को इसका लाभ हुआ और वह सार्वजनिक सेवा कार्यक्रमों में निवेश कर सका।

US WTI Crude Oil का वायदा भाव नेगेटिव होने पर

MCX ने भारत में 1 रुपये तय की सेटलमेंट प्राइस, हुआ विवाद

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोमवार रात मई महीने के क्रूड ऑयल WTI का वायदा भाव शून्य से नीचे आ गया था। 21 अप्रैल को पूरे हुए इस मई अनुबंध के यूएस WTI क्रूड ऑयल का वायदा भाव सोमवार रात -37.63 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गया था। वहीं, एमसीएक्स पर अप्रैल महीने का क्रूड ऑयल का अनुबंध, सोमवार को शाम पांच बजे 965 रुपये प्रति बैरल पर बंद हुआ है। इसके बाद एमसीएक्स ने सोमवार देर रात एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उसने लिखा, 'अनुबंध की सेटलमेंट प्राइस अभी के लिए एक रुपया प्रति बैरल तय की जाती है और अंतिम निर्णय के बारे में घोषणा कर दी जाएगी।'

भारत के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स द्वारा अंतरिम सेटलमेंट प्राइस को एक रुपये प्रति बैरल तय करने से अब कुछ कारोबारियों का कहना है कि एमसीएक्स ने यह कदम बड़े ब्रोकर्स को करोड़ों रुपये के नुकसान से बचाने के लिए उठाया है। दरअसल, एमसीएक्स पर अप्रैल महीने का क्रूड का वायदा बाजार सोमवार शाम ही बंद हो जाने से भारत के और यूएस के भाव में काफी बड़ा अंतर आ गया है। भारत में यह 965 रुपये प्रति बैरल पर बंद हुआ है और यूएस क्रूड ऑयल NYMEX पर सोमवार रात -37 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा था।

इस तरह गणना करें तो यूएस और भारत के सेटलमेंट प्राइस में 3,777 रुपये प्रति बैरल का अंतर है। इस गणना में एक डॉलर की कीमत 76 रुपये मानी गई है। जिसके अनुसार (-37x76= -2812)+965 =3,777 रुपये है। इस गणना में मई वायदा के यूएस क्रूड WTI के भाव -37 डॉलर को 76 से गुणा किया जिससे इसका रुपये में मूल्य -2812रुपये आया। अब एमसीएक्स पर अप्रैल अनुबंध के लिए बंद हुए क्रूड ऑयल के भाव 965 रुपये को इसमें जोड़ा तो कुल 3,777 रुपये आए।

न्यूज एजेंसी पीटीआइ के सूत्रों के अनुसार, सेबी इस स्थिति से अवगत है और सक्रिय रूप से इस मुद्दे को देख रही है। हालांकि, यह मामला अब सरकारी अथॉरिटीज तक भी पहुंच गया है। अथॉरिटीज चाहती हैं कि अगर एक्सचेंज ने नियमों के खिलाफ काम किया है या किसी विशेष ब्रोकर को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया है, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। मंगलवार दोपहर खबर लिखते समय एमसीएक्स एक्सचेंज पर 18 मई 2020 के क्रूड ऑयल का वायदा भाव 17.95 फीसद या 318 रुये की गिरावट के साथ 1454 रुपये प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा था।

News यू केन USE

तेल कीमतों में गिरावट के बाद ट्रंप ने बनाई राष्ट्रीय भंडार को भरने की योजना

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि वह तेल कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट का इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रीय सामरिक

भंडार को फिर से भरने के लिए करेंगे। ट्रंप ने कोरोना वायरस महामारी के संबंध में अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम अपने राष्ट्रीय पेट्रोलियम भंडार भर रहे हैं... आप जानते हैं, सामरिक भंडार।" उन्होंने कहा, "हम भंडार में 7.5 करोड़ बैरल भरना चाहते हैं।" उन्होंने बाद में यह स्पष्ट किया कि वह यह खरीदारी तभी करेंगे, जबकि अमेरिकी संसद इसके लिए धन को मंजूरी देगी। इसके अलावा अमेरिकी सरकार इस भंडार को किसी तीसरे पक्ष को किराए पर भी दे सकती है। जब कीमतें बढ़ेंगी, तो ये विक्रेता अतिरिक्त तेल बेच सकते हैं। अमेरिका में सोमवार को तेल कीमतें अप्रत्याशित रूप से पहली बार नकारात्मक हो गई थीं, हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सुधार हुआ।

ओपेक, अन्य देशों ने तेल बाजार की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की

वियना। एजेंसी

कच्चे तेल के दाम रसातल पर पहुंचने के बीच तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कहा है कि उसके सदस्य देशों के कई मंत्रियों और ओपेक के कुछ अन्य सहयोगियों ने मंगलवार को टेलीकन्फ्रेंसिंग की है। इस दौरान वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम पर चर्चा की गई। ओपेक ने ट्वीट कर कहा है कि सदस्यों ने तेल बाजार की मौजूदा अप्रत्याशित स्थिति पर गहन चर्चा की। हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सऊदी अरब और रूस जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने इसमें भाग लिया अथवा नहीं।

तालों में बंद तेल का किसको फायदा?

ONGC, OIL इंडिया को महंगा पड़ रहा सस्ता क्रूड

मुंबई। एजेंसी

तेल अगर तालों में बंद हो तो उसका क्या फायदा? और अब तो हालत ऐसी हो गई है कि धरती के अंदर से निकाले जा रहे तेल को ऊपर रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। हाल में क्रूड ऑइल के नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के नेगेटिव जोन में चले जाने की बड़ी वजह यही रही। BPCL, HPCL और IOC जैसी ऑइल मार्केटिंग कंपनियों के लिए क्रूड ऑइल का सस्ता होना खुशखबरी है, लेकिन इसको वे एंजॉय तभी कर पाएंगी जब उनकी मांग में सुधार होगा। कुछ एनालिस्टों का मानना है कि इसके उलट क्रूड ऑइल का दाम कमजोर बने रहने से ओएनजीसी और ऑइल इंडिया जैसी ऑइल एक्सप्लोरेशन और प्रॉडक्शन कंपनियों के प्रॉफिट में तेज गिरावट आएगी। सोमवार को वायदा बाजार में WTI क्रूड का भाव जीरो से नीचे चला गया था। यह ठीक उसी तरह हुआ था जिस तरह लाखों करोड़ डॉलर के बॉन्ड नेगेटिव जोन में चले गए थे। ऐसा इसलिए हुआ कि ऑइल के बड़े उपभोक्ता देशों में कोरोना वायरस से फैली महामारी के चलते लॉकडाउन है और जमीन से निकाले गए क्रूड को रखने के लिए जगह कम पड़ती जा रही है। शेयरखान के एनालिस्ट अभिजीत बोरा के मुताबिक, 'रिफाइनरी फ्यूल लॉस कम होने और ऑटो फ्यूल का मार्केटिंग मार्जिन ज्यादा होने से IOCL, BPCL और HPCL जैसी ऑइल मार्केटिंग कंपनियों को सस्ते क्रूड का फायदा मिलेगा।

लेकिन लॉकडाउन के चलते उनको नियर टर्म में पेट्रोलियम की कमजोर डिमांड और इनवेंटरी लॉस का सामना करना पड़ेगा।' HPCL, BPCL और IOC के शेयरों में मंगलवार को 5-5% की गिरावट आई जबकि ONGC का शेयर लगभग 7% फिसल गया। ऑइल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में पहले ही बड़ा करेक्शन हो चुका है और उनमें हिस्टोरिक बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है। BPCL और HPCL का शेयर 52 वीक से 35% नीचे आ चुका है जबकि IOC के शेयरों में पीक प्राइस के आधे पर ट्रेड हो रहा है। IIFL इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट हर्षवर्धन डोले कहते हैं, 'ऑइल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों के दाम में ज्यादा गिरावट आने के आसार नहीं हैं लेकिन इनकी रीरेटिंग कराने लायक कोई ट्रिगर भी नजर नहीं आ रहा है।' पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स का नेट मार्केटिंग मार्जिन नॉर्मल मार्जिन का लगभग 7 गुना हो गया है। ऐनालिस्ट बताते हैं कि क्रूड के दाम में प्रति बैरल 1 डॉलर की गिरावट आने से पेट्रोल और डीजल का नेट मार्केटिंग मार्जिन 0.45 रुपये प्रति लीटर बढ़ता है। रिलायंस सिक्योरिटीज के रिसर्च ऐनालिस्ट योगेश पाटिल कहते हैं, 'ऑइल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का नेट मार्केटिंग मार्जिन मिल रहा है जो क्रूड के दाम में आ रही गिरावट के चलते बढ़ सकता है। क्रूड ऑइल सस्ता होने से FY21 में ऑइल मार्केटिंग कंपनियों के मार्केटिंग इबिट्डा में तेज उछाल आ सकती है।'

ओएनजीसी ने कच्चे तेल की गिरती कीमतों के मद्देनजर सरकार से उपकर, रॉयल्टी माफ करने की मांग की

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने कच्चे तेल की कीमतों में लगातार आती गिरावट के मद्देनजर सरकार से उपकर और रॉयल्टी माफ करने की मांग की है। कंपनी का कहना है कि कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव इतने नीचे आ चुके हैं कि उनसे कंपनी की परिचालन लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें दो दशक से भी अधिक समय के निचले स्तर पर आ गयी हैं। यह एक ओर उपभोक्ताओं के लिये अच्छी खबर है लेकिन तेल एवं गैस उत्पादकों पर इसके कारण भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, ओएनजीसी प्रबंधन ने सरकार को बताया है कि अप्रैल में उसे 22 डॉलर प्रति बैरल के औसत भाव मिले हैं, जो कि उसकी परिचालन की लागत से भी कम है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस की कीमतें 2.39 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के एक दशक के निचले स्तर पर आ जाने से कंपनी को सालाना करीब छह हजार करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, ओएनजीसी प्रबंधन ने सरकार से कहा है कि यदि उत्पादकों को मिलने वाला औसत भाव 45 डॉलर प्रति बैरल से कम हो तो ऐसी स्थिति में तेल खोज उपकर को समाप्त किया जाना चाहिये। इसके साथ ही प्रबंधन ने अपतटीय इलाकों से उत्पादित होने वाले तेल एवं गैस पर केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाने वाली रॉयल्टी से भी छूट दिये जाने की मांग की है। सरकार तेल उत्पादकों को मिलने वाले भाव पर 20 प्रतिशत उपकर वसूलती है। इसके अलावा ओएनजीसी तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड को जमीनी तेल खंडों से निकाले जाने वाले कच्चे तेल की एवज में राज्य सरकारों को 20 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है। केंद्र सरकार अपतटीय इलाकों से निकाले जाने वाले तेल एवं गैस पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक की रॉयल्टी वसूल करती है। सूत्रों के अनुसार, कंपनी चाहती है कि फिलहाल उसे केंद्र सरकार द्वारा वसूली जाने वाले रॉयल्टी से छूट दी जाये। कंपनी ने कहा है कि घरेलू तेल एवं गैस क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिये कीमत निर्धारण का वह तरीका अपनाया जाये जो रूस और अमेरिका जैसे गैस-सरप्लस देशों की कीमतों पर आधारित हो। यदि इस तरीके का इस्तेमाल किया जाये तो अप्रैल से प्राकृतिक गैस की दरें 2.39 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आ सकतीं हैं।

चीन से भारत आने वाली कंपनियों के लिए खास प्लान, मिलेगा इन्सेंटिव

नई दिल्ली। एजेंसी

चीन से अपनी फैक्ट्रियों को भारत शिफ्ट करने पर विचार करने वाली कंपनियों को भारत में खास फायदा दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक योजना तैयार कर रहे हैं जिसमें चीन में मैन्युफैक्चरर्स को फैक्ट्रियां भारत शिफ्ट करने पर इन्सेंटिव देने का कदम शामिल होगा। ये इन्सेंटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेज की भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के इरादे से दिए गए इन्सेंटिव के समान होंगे। कोरोनावायरस के संकट के बाद बहुत-सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन को एक ही स्थान पर सीमित नहीं करना चाहतीं। सरकार उन कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए कई ग्रुप बनाएगी जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया, 'इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेज जैसे इन्सेंटिव कुछ अन्य सेक्टर्स को भी दिए जा सकते हैं। इस पर विचार किया जा रहा है।'

अधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के साथ ही अतिरिक्त इन्सेंटिव देने से भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता वियतनाम के जैसी हो जाएगी। सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को घटाकर बिना किसी इन्सेंटिव के 22 पर्सेंट कर दिया था। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह 15 पर्सेंट का है।

DPIIT के पास पहले ही ऐसे राज्यों की सूची है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉजेक्ट्स के लिए जल्द क्लियरेंस दे सकते हैं और जिनके पास जमीन के बड़े टुकड़े भी हैं। अधिकारी ने बताया, 'बहुत से देश अब चाहते हैं कि उनकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग को डायवर्सिफाई करे।' उन्होंने कहा कि भारत ने चीन के विकल्प के तौर पर एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनने के लिए अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके साथ ही देश में एक बड़ा मार्केट भी है जो अन्य देशों की तुलना में एक अतिरिक्त लाभ है।

सरकार ने इस बारे में ऐसी लगभग 100 एमएनसी के साथ बातचीत की है जिनकी चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो वहां से बाहर निकलना चाहती हैं। जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चीन से शिफ्ट होने में मदद के लिए 2.2 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। चीन में कोरोना वायरस के फैलने की वजह से सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा है।

भारत का इससे पहले फोकस ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने पर था, लेकिन अब सरकार देश को सप्लाई चेन के बड़े कंपोनेंट्स और फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स का हब बनाना चाहती है। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य चीन से महत्वपूर्ण प्रॉडक्ट्स के इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना भी है। इसके लिए एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स जैसे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण रॉ मैटीरियल का देश में प्रॉडक्शन बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। देश की कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी चीन से बड़े पैमाने पर कंपोनेंट्स का इम्पोर्ट करती हैं।

सऊदी अरब की तेल बाजारों पर करीबी नजर, कर सकता है हस्तक्षेप

रियाद। एजेंसी

तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक में अहम ओहदा रखने वाले देश सऊदी अरब ने मंगलवार को कहा कि तेल बाजार पर उसकी करीबी नजर है। उसने कहा कि कीमतों के ऐतिहासिक निचले स्तर पर चले जाने के बाद वह अतिरिक्त कदम उठाने को तैयार है। सउदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी ने एक सरकारी बयान के हवाले से कहा, ''सरकारी प्रशासन की तेल बाजार के हालातों पर करीबी नजर है। वह ओपेक और अन्य सहयोगी देशों (ओपेक प्लस) के साथ मिलकर अतिरिक्त कदम उठाने को तैयार है।

ट्रंप ने शेवरॉन को वेनेजुएला में तेल क्षेत्रों से उत्पादन रोकने को कहा

कराकस (वेनेजुएला)। एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर सत्ता छोड़ने के लिये दबाव बढ़ाते हुए मंगलवार को अमेरिकी कंपनी शेवरॉन कार्पोरेशन को एक दिसंबर तक वेनेजुएला में उत्पादन गतिविधियां बंद करने को कहा है। इस दौरान कंपनी को वहां तेल की खोज और निर्यात पर भी रोक लगाने को कहा गया है। शेवरॉन अमेरिका की आखिरी बड़ी कंपनी है जो कि संकटग्रस्त वेनेजुएला में कारोबार कर रही है। उसने दक्षिण अमेरिका स्थित इस देश के तेल क्षेत्रों में तेल खोज और मशीनरी आदि में पिछली सदी के दौरान 2.6 से अरब डालर का अनुमानित निवेश किया है। विश्लेषकों का मानना है कि मादुरा सरकार इन संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती है। वेनेजुएला की मादुरो सरकार के खिलाफ अमेरिका की तरफ से उठाये जाने वाले कदमों में की यह ताजा कड़ी। इसके साथ ही अमेरिका ने मादुरो की सत्ता को समाप्त करने की रफ्तार तेज कर दी है। यदि वेनेजुएला से मादुरो की सत्ता समाप्त होती है तो यह वेनेजुएला में 20 साल के समाजवादी शासन का अंत होगा। आलोचकों का कहना है कि इस समाजवादी शासन के कारण ही किसी समय दुनियाभर में तेल उत्पादन के लिहाज से सबसे अमीर देशों में गिनती रखने वाले वेनेजुएला का आर्थिक और राजनीतिक पतन हुआ है। वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं लेकिन इसके बावजूद इस देश की राजनीतिक उठापटक और आर्थिक संकट की वजह से इसके 45 लाख से अधिक लोगों को हाल के वर्षों में अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। इनका मानना है कि देश में पानी, बिजली, पेट्रोल और बेहतर अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है।

क्रूड की गिरावट से कारोबारियों और एक्सचेंज को हुआ भारी नुकसान

मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज पर कारोबार के समय में बदलाव

मुंबई। क्रूड में मचे हाहाकार से ट्रेडर और एक्सचेंज को हुए भारी नुकसान के बाद एमसीएक्स पर ट्रेडिंग के टाइम में बदलाव करना पड़ा है। एमसीएक्स पर अब नॉन- एग्री कमोडिटीज ट्रेडिंग सिर्फ 9 बजे सुबह से 11:30 बजे तक ही होगी। नया ट्रेडिंग टाइम 23 अप्रैल से लागू होगा। बता दें कि सेटलमेंट प्राइस में दिक्कत की वजह से ट्रेडिंग समय बदला गया है।

कारोबारियों को हुआ था भारी नुकसान

बता दें कि क्रूड के निगेटिव में जाने से ट्रेडर, एक्सचेंज को भारी नुकसान का सामाना करना पड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉन्ग पोजिशन में 418 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जिसे देखते हुए नॉन-एग्री कमोडिटीज ट्रेडिंग और अन्य कमोडिटीज के वक्त में बदलाव किया गया है। नॉन-एग्री कमोडिटीज ट्रेडिंग 9 बजे सुबह से 11:30 बजे रात तक होगी जबकि अन्य कमोडिटीज में ट्रेडिंग का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

25 को भी बदला था समय

देश के सबसे बड़े जिंस वायदा बाजार प्लेटफॉर्मएमसीएक्स ने लॉकडाउन से अब कुछ रियायत मिलने के बाद यह कदम उठाया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने देश भर में 25 मार्च से बंद से पहले जिंस बाजारों से मार्च के मध्य से ही कोविड-19 के कारण व्यापक स्तर पर उतार-चढ़ाव रोकने के लिए कारोबारी समय कम करने को कहा गया था। इसके बाद 14 अप्रैल तक कारोबारी समय 9.00 बजे से रात 11.30 बजे तक को घटाकर सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे कर दिया गया। बंद का पहला चरण 14 मार्च को ही समाप्त होना था, लेकिन इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब सरकार ने एहतियाती उपायों के साथ 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में बंद से थोड़ी राहत दी है।

अन्य कमोडिटीज में 5 बजे तक होगा कारोबार

बयान के अनुसार बाजार प्रतिभागियों से मिली जानकारी और सेबी के साथ विचार-विमर्श के बाद 23 अप्रैल से कारोबारी समय संशोधित करने का फैसला किया गया है। इसके तहत गैर-कृषि जिंसों का कारोबार सुबह 9.00 बजे रात 23.30 तक होगा, जबकि अन्य कमोडिटीज (कपास, सीपीओ और आरबीडी पॉमोलीन समेत) के मामले में कारोबार अगले नोटिस तक शाम 5.00 बजे तक होगा।

कोरोना वायरस संक्रमण थामने के लिये एम्स में परीक्षण के तौर पर उपयोग होगा रोबोट

नयी दिल्ली। रोबोट और प्रौद्योगिकी उत्पाद बनाने वाली कंपनी मिलाग्रो ने मंगलवार को कहा कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये परीक्षण के तौर पर उसके दो रोबोट का उपयोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में किया जाएगा। मिलाग्रो ने एक बयान में कहा कि मिलाग्रो आईमैप9 फर्श को स्वच्छ और संक्रमण मुक्त करने वाला रोबोट है।

इसमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। यह आईसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) की सिफारिश के अनुसार सोडियम हाइपोक्लोराइट समाधान का उपयोग कर फर्श के जरिये कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को समाप्त करता है।

वहीं मिलाग्रो ह्यमनोआइड ईएलएफ डाक्टरों को कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों से दूर रहकर बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराता है। इससे संक्रमण फैलने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, ''मिलाग्रो फ्लोर रोबोट आईमैप9.0 और मिलाग्रो ह्यमनोआइड का परीक्षण के तौर पर उपयोग दिल्ली के एम्स में किया जाएगा।'' मिलाग्रो के संस्थापक चेयरमैन राजीव करवाल ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद के लिये कंपनी काफी खुश है और वास्तविक स्थिति को लेकर प्रतिक्रिया के आधार पर और उत्पादों का विकास किया जाएगा।

शराब विनिर्माताओं की दिल्ली सरकार से लाइसेंस शुल्क में रियायत की अपील

नयी दिल्ली। एजेंसी

शराब विनिर्माताओं ने दिल्ली सरकार से लॉकडाउन (पाबंदी) की अवधि के लाइसेंस शुल्क आदि माफ करने की आपील की है। दिल्ली सरकार ने पाबंदियों के बीच लाइसेंस की मियाद तीन माह और बढ़ा कर 30 जून तक कर दी है पर इस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर शुल्क जमा करने को कहा है।कंफडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहॉलिक बेवरेजेस कंपनीज (सीआईएबीसी) के अनुसार अधिकतर राज्य सरकारों ने लाइसेंस और अन्य शुल्क माफ कर दिए हैं। जबकि लॉकडाउन (बंद) की वजह से सारा काम बंद होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने लाइसेंस शुल्क देने के लिए कहा है।सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा कि बंद की वजह से दिल्ली में पूरा थोक और खुदरा शराब कारोबार 22 मार्च से बंद है। ऐसे में सरकार के परामर्श पर कंपनियां कर्मचारियों को वेतन-भत्तों का भुगतान कर रही हैं। इससे कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव है। ऐसे में कारोबार नहीं होने की अवधि के लिए हम नवीनीकरण शुल्क जमा कराने में सक्षम नहीं है।दिल्ली के आबकारी आयुक्त को लिखे पत्र में सीआईएबीसी ने सरकार से मौजूदा एल1, एल1-एफ और एल2 लाइसेंसों की वैधता 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

कर्मचारियों को करना पड़ रहा आवाजाही प्रतिबंधों का सामना : हिंदुस्तान यूनिलीवर

नयी दिल्ली। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का कहना है कि भले उसके संयंत्र परिचालन में हैं लेकिन उनमें पूरी क्षमता से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में उसके कर्मचारियों को स्थानीय प्रशासन के आवाजाही प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन (बंद) किया गया है। इस वजह से लोगों की आवाजाही और विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। लेकिन आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगी कंपनियां लगातार उत्पादन कर रही हैं। हिंदुस्तान युनिलीवर साबुन, टूथपेस्ट और इंस्टेंट नूडल्स जैसे रोजमर्रा उपभोग के उत्पादन बनाती है।कंपनी ने कहा कि वह कर्मचारियों को प्रतिबंध से राहत दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है।कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, '' हमारे अधिकतर कारखाने, वितरण केंद्र और आपूर्तिकर्ता परिचालन कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे।''उन्होंने कहा, ''अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में काम कर रहे हमारे कर्मचारी लगातार स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों के प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के साथ काम करना जारी रखा है। ताकि हम उस क्षमता से अपने कारखानों को चला सकें जिसकी उम्मीद देशवासी हमसे रखते हैं।''प्रवक्ता ने कहा कि उपलब्ध कर्मचारियों का युक्तिसंगत उपयोग करने के लिए कंपनी सिर्फ बड़े ऑर्डर ले रही है और सीधे कारखानों से आपूर्ति कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के देशभर में 28 कारखाने हैं। कंपनी में लगभग 18,000 लोग काम करते हैं।

कोरोना महामारी

टेक्नॉलजी की मदद से पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था, थिंक टैंक कर रहा काम

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी से पस्त हुई अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार का एक थिंकटैंक एक पॉलिसी पेपर पर काम कर रहा है। यह थिंकटैंक इकॉनमी को जल्द से जल्द पटरी पर लाने के लिए किस टेक्नॉलजी का इस्तेमाल किया जाए, इसपर सरकार को सुझाव देगा। स्टडी के बाद पॉलिसी पेपर प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष पेश किया जाएगा। यह पॉलिसी पेपर साइंस ऐंड टेक्नॉलजी डिपार्टमेंट के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान टेक्नॉलजी, इन्फॉर्मेशन, फॉरेकास्टिंग ऐंड असेसमेंट काउंसिल (TIFAC) कर रहा है, जो मूलतः मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करने, देसी तकनीक का वाणिज्यिकरण, तकनीक आधारित पारदर्शी जनवितरण प्रणाली विकसित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सक्षम करना तथा आयात कम करने पर केंद्रित होगा। यह थिंकटैंक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, मशीन

लर्निंग तथा डेटा ऐनालिटिक्स जैसी उभरती तकनीकों को अपनाने के तरीके सुझाएगा। TIFAC के कार्यकारी निदेशक प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि पेपर प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी विकसित तथा विकासशील दोनों तरह के देशों में मानव जीवन पर असर डाल रहा है और यह प्रभाव लगभग सभी क्षेत्रों जैसे मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एजुकेशन तथा हेल्थकेयर पर पड़ा है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि महामारी कितनी फैलती है और इसे रोकने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नॉलजी आशुतोष शर्मा ने कहा, 'इस तरह, तकनीक आधारित इच्छित हस्तक्षेप और विभिन्न सेक्टर्स पर उसके प्रभाव का विश्लेषण फैसला लेने का आधार होगा।'

कमजोर मांग से रिफाइंड सोयातेल वायदा कीमतों में गिरावट

नयी दिल्ली। एजेंसी

हाजिर बाजार की कमजोर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों की कटान की जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को रिफाइंड सोया की कीमत 16.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 749.2 रुपये प्रति 10 किग्रा रह गयी। एनसीडीईएक्स में रिफाइंड सोया के मई माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 16.4 रुपये या 2.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 749.2 रुपये प्रति 10 किग्रा रह गयी। इसमें 25,000 लॉट के लिए कारोबार हुआ। रिफाइंड सोया के जून माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 15.8 रुपये या 2.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 725.2 रुपये प्रति 10 किग्रा रह गयी। इसमें 7,500 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि पर्याप्त स्टॉक के मुकाबले कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से मुख्यतः रिफाइंड सोया वायदा कीमतों में गिरावट आई।

ई-नाम से जुड़े 11.37 लाख ट्रक, 2.3 लाख ट्रांसपोर्टर: कृषि मंत्रालय

नयी दिल्ली। कोविड-19 महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाऊन के दौरान कृषि उत्पादों को मंडी से अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पर 11.37 लाख ट्रक और 2.3 लाख ट्रांसपोर्टरों ने खुद को पंजीकृत कराया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि वस्तुओं के संग्रहकर्ता के तहत इन सभी का पंजीकरण किया गया है जिसे हाल ही में ई-नाम मंच पर पर पेश किया गया था ताकि व्यापारियों को मंडियों से वस्तुओं की जल्दी आपूर्ति करने के लिए अपने आसपास के ट्रांसपोर्टरों का पता लगाने में मदद मिल सके। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''11.37 लाख से अधिक ट्रक और 2.3 लाख ट्रांसपोर्टर पहले से ही इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं।'' मौजूदा समय में, 16 राज्यों में 585 मंडियों (कृषि-बाजार) और दो केंद्र शासित प्रदेशों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है, जिसमें 1.66 करोड़ किसान, 1,28,000 व्यापारी और 70,934 कमीशन एजेंटों का उपयोगकर्ता आधार शामिल है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को खेत से लेकर मंडियों तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने में मदद करने के लिए 'किसान रथ' नामक एक मोबाइल एप जारी किया गया है। मोबाइल एप को ई-नाम और गैर-ई-नाम दोनों प्लेटफार्मों के उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान मंडियों में भीड़ को कम करने के लिए, मंत्रालय किसानों को ई-नाम प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर-राज्यीय आवाजाही के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं और फलों और सब्जियों की आपूर्ति के साथ कीमतों की निगरानी के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।

लीची की मिठास और आम की खुशबू को लगी कोरोना की नजर, किसान उठाएंगे नुकसान और दुनिया गंवाएगी स्वाद

पटना। एजेंसी

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह देश में लागू लॉकडाउन के चलते कई आर्थिक नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के लीची और आम के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण के साथ बेगुसराय, भागलपुर और सीतामढ़ी के लीची किसान परेशान हैं। इस बार मौसम अनुकूल रहने की वजह से पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के कारण उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे। बता दें कि बिहार में लीची का कारोबार एक हजार करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें सिर्फ मुजफ्फपुर से ही करीब 500 करोड़ का लीची व्यापार होता है। लेकिन इसबार अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना की वजह से लीची की खेती करने वाले किसानों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पैदावार तो अच्छी, लेकिन होगा नुकसान

हालांकि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के निदेशक विशाल नाथ ने नवभारत टाइम्स.कॉम को बताया कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। क्योंकि बिहार में लगभग 50 फीसदी किसानों के लीची बगान को बड़े वेंडर द्वारा निश्चित राशि के तय कर चार से पांच साल के लिए खरीद लिया जाता है। इस कांट्रेक्ट से किसानों को घाटा होने डर लगभग समाप्त हो जाता है। इसके अलावा 30 फीसदी ऐसे वेंडर भी होते हैं जो एक से दो साल के लिए बगान को खरीदते हैं। शेष बचे 20 फीसदी किसान फसल की पैदावार करने से लेकर उसे मार्केट में बेचने का काम करते हैं। ऐसे किसानों के पास मई के दूसरे सप्ताह में खरीददार पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार लीची की पैदावार अच्छी हुई है। 20 मई के बाद लीची की फसल बेचने के लिए तैयार भी हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसपर बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि तैयार फसल को बाहर ले जाने के लिए बाक्स और ट्रांस्पोटेशन की भी समस्या भी आ सकती है।

लीची ग्रोवर्स एसोशिएशन का क्या कहना है

बिहार के लीची ग्रोवर्स एसोशिएशन के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि इस बार मौसम की अनुकूलता की वजह से ना सिर्फ पैदावार अच्छी होगी, बल्कि फसल भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि ओलावृष्टि भी हुई है, लेकिन इसका ज्यादा नुकसान फसल को नहीं हुआ है और मई से फसल आनी भी शुरू हो जाएगी। मुश्किल यह है कि इस बार खरीददार

नहीं मिल रहे। इसके अलावा कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से परेशान और पैसों की कमी की वजह से लोगो में खरीदारी क्षमता भी कम हो रही है। इससे लीची के व्यवसाय पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है।

मुंबई और दिल्ली में बिहार के लीची की खपत

लीची ग्रोवर्स एसोशिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि बिहार से 1500 टन लीची दिल्ली तो 1000 टन मुंबई के मार्केट में पहुंचते थे। लेकिन अब दोनों शहर कोरोना वायरस की वजह से 'रेड जोन' में है। ऐसे में उन्हें ग्रीन जोन तक पहुंचने में महीने भर से उपर का समय लगेगा और तबतक लीची की पैदावार खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई - दिल्ली के अलावा जयपुर, पुणे और लखनउ से भी खरीदार आते थे, लेकिन इसबार कोई नहीं पहुंचा। बच्चा प्रसाद सिंह ने यह भी बताया कि दो महीने पहले उन्हे केंद्रीय कृषि मंत्रालय से दिल्ली बुलाया गया था, जिसमें मंत्रालय के सचिव से बातचीत में लीची को लेकर कृषि उडान योजना में मदद की बात हुई थी। इस बैठक में विमान कंपनी और रेलवे के अधिकारी भी लीची के ट्रांसपोटेशन को लेकर शामिल हुए थे।

कोरोना का असर आम पर भी

बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सबौर के एसोसिएट डायरेक्टर फैज अहमद ने बताया कि बिहार में लीची, अमरूद, केला और आम की पैदावार ज्यादा होती है। इसमें आम का स्थान 64 फीसदी पैदावार के साथ पहले नंबर पर है। उन्होंने बताया कि इस बार आम के पेड़ में मंजर आने के साथ ही उसका मिलन बारिश के साथ हो गया था। इसकी वजह से 10 से 12 फीसदी तक मंजर खराब हो गये। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डायरेक्टर ने बताया कि बिहार में 1 लाख 30 हजार हेक्टेयर में आठ से 10 लाख टन तक आम की पैदावार होती है। इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से किसानों को 20 से 30 फीसदी तक का घाटा उठाना पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि कुल उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत तक आम पश्चिम बंगाल जाता था। इस बार इसकी संभावना कम ही दिख रही है, क्योंकि 3 मई के बाद लॉकडाउन की स्थिति क्या होगी अभी कहना मुश्किल है। इसके अलावा लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बाहर के कितने व्यापारी बिहार आएंगे, यह भी बता पाना मुश्किल है।

कृषि विभाग ने किसानों की परेशानी दूर करने के लिए उठाया कदम

बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य में जारी लॉकडाउन के कारण इन फसलों को कम से कम नुकसान हो। इसके लिए कृषि विभाग विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा है। आम एवं लीची की फसल को किट व्याधियों से बचाने के लिए भी कार्य किये जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी मार्केटिंग के लिए सभी जिला कृषि पदधिकारियों एवं उद्यान पदधिकारियों को खास निरदेश भी दिये गये हैं। उनसे कहा गया है कि जिला स्तर पर आम एवं लीची से जुड़े राज्य के या फिर राज्य के बाहर के व्यवसायी जो पहले इन जिलों से आम और लीची का व्यापार करते थे, उनसे संपर्क करें। आम एवं लीची तथा अन्य सभी कृषि उत्पादों के राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर परिवहन हेतु सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा तथा व्यवसायियों को सरकार के स्तर से सभी तरह का सहयोग किया जाएगा।

शाही लीची एवं जर्दालु आम को 'जी आई टैग'

कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य के शाही लीची एवं जर्दालु आम को 'जी आई टैग' मिला है, जिसके फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य में सरप्लस फल सब्जियों के प्रोसेसिंग के लिए भी योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना के तहत छोटे स्तर पर फलों सब्जियों के शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग आदि के लिए 10 लाख की इकाई स्थापित करने वालों को 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा भी राज्यों से कृषि उत्पादों के अंतरराज्यीय परिवहन हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। इसका भी राज्य के किसानों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर विभाग का प्रयास है कि राज्य के किसानों को इस लॉकडाउन से कोई नुकसान न हो। इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

कोविड-19 से अर्थव्यवस्था को 'अप्रत्याशित' झटका, कंपनियां भविष्य को लेकर अनिश्चितः सर्वे

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी का भारतीय कंपनियों पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से पिछले कुछ सप्ताह के दौरान आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से 'ठप्प' पड़ गई हैं। मंगलवार को उद्योग के एक सर्वे में यह बात कही गई है। उद्योग मंडल फिक्की और कर परामर्शक ध्रुव एडवाइजर्स द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वे में विभिन्न क्षेत्रों की करीब 380 कंपनियों की राय ली गई। सर्वे में कहा गया है कि इस महामारी की वजह से कंपनियां अपने भविष्य को लेकर काफी ज्यादा अनिश्चित हैं। सर्वे में शामिल 72 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि

मौजूदा स्थिति का उनके कारोबार पर 'बड़ा और काफी ज्यादा' प्रभाव पड़ा है। यही नहीं इस संकट की वजह से बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है। सर्वे में शामिल 75 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि आगामी महीनों मे वे अपने कर्मचारियों की संख्या में कुछ कटौती करेंगी। अच्छी-खासी संख्या में कंपनियों ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में उनकी बिक्री का परिदृश्य सकारात्मक नहीं रहेगा। 70 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि 2020-21 में उनकी बिक्री में गिरावट आएगी। इसके अलावा ज्यादातर कंपनियों ने कहा कि उनकी कारोबारी नकदी और आर्डर बुक में भी कमी आएगी। फिक्की ने बयान में कहा, "सर्वे से यह तथ्य सामने आया है कि सरकार की ओर से उद्योग को बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं मिलता है तो बड़ी संख्या में कंपनियों के लिए इस स्थिति से उबर पाना मुश्किल होगा।"

डेमलर इंडिया ने भारत बेंज वाहनों के लिए वॉरंटी, सर्विस की अवधि दो महीने बढ़ाई

नयी दिल्ली। डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (डीआईसीवी) ने लॉकडाउन की वजह से अपने भारतबेंज वाहनों के लिए वॉरंटी और सर्विस की अवधि दो माह बढ़ा दी है। कंपनी ने बयान सभी भारतबेंज ट्रक और बस ग्राहकों को वाहनों पर दो माह की वॉरंटी मुफ्त मिलेगी। डीआईसीवी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सत्यकाम आर्य ने कहा, "यहां तक राष्ट्रवापी बंद के दौरान भी भारतबेंज के ग्राहक आवश्यक जिंसों की आपूर्ति कर रहे हैं। उन लोगों को समर्थन के लिए हमने सर्विस और वॉरंटी दो माह के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।" कंपनी ने कहा कि इस पहल के तहत भारतबेंज के जिन वाहनों पर वॉरंटी अनुबंध 15 मार्च, 2020 से 15 मई, 2020 के दौरान समाप्त हो रहा है या इस अवधि के दौरान उनके वाहन की सर्विस होनी है, को अब इसके लिए दो माह अतिरक्त मिलेंगे।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पर सेंसेक्स 743 अंक उछला

मुंबई। एजेंसी

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स बुधवार को 743 अंक की बढ़त के साथ 31,379.55 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक रुख के बीच सेंसेक्स में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंस्ट्रीज के शेयर में जोरदार तेजी से बाजार को मजबूती मिली। रिलायंस जियो में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिये फेसबुक के 5.7 अरब डॉलर (43,574) के निवेश की घोषणा से कंपनी का शेयर 10 प्रतिशत उछला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारण सेंसेक्स में 350 अंक से अधिक की तेजी आयी। तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 742.84 अंक यानी 2.42 प्रतिशत बढ़कर 31,379.55 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205.85 अंक यानी 2.29 प्रतिशत मजबूत होकर 9,187.30 अंक पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई जियो के प्लेटफार्म में निवेश के साथ फेसबुक उसमें सबसे बड़ी अल्पांश हिस्सेदार बन गयी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा एशियन पेंट्स, इंडसइंडबैंक, नेस्ले इंडिया, मारुति, हीरो मोटो कार्प और एचयूएल में भी तेजी रही। इन कंपनियों के शेयरों में 5 प्रतिशत तक की मजबूती आयी। वहीं दूसरी तरफ ओनजीसी, एल एंड टी और पावरग्रिड नुकसान में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सोल लाभ के साथ बंद हुए जबकि तोक्यो शेयर बाजार में गिरावट रही। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी दर्ज की गयी। इस बीच, ब्रेंट क्रूड वायदा का भाव 2.16 प्रतिशत टूटकर 18.91 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 76.68 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित हुए भगवान परशुराम

शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए ही हो, ऐसी व्यवस्था भगवान परशुराम जी ने की। अधर्म के प्रति सदैव क्रोध परायण रहने वाले भगवान परशुराम जी ने अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दी और उनके आदेशानुसार स्वयं महेन्द्र पर्वत पर चले गए।

जब-जब यह पृथ्वी असुरों एवं अत्याचारियों के अत्याचार से त्रस्त हुई तथा जब-जब मानव जाति के लिए अधर्मियों ने संकट पैदा किए, तब-तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका संहार करने के लिए अवतार धारण किए।

भगवान विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को समस्त सनातन जगत के आराध्य भृगुकुल शिरोमणि भगवान परशुराम जी ने पिता महर्षि जमदग्नि तथा माता रेणुका के गर्भ से जन्म लिया। पितामह भृगु ने सर्वप्रथम इनका नामकरण राम किया परन्तु भगवान शिव द्वारा प्रदान किए परशु को धारण करने से यह परशुराम हो गए। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त शारंग धनुष महर्षि ऋचीक ने अपने पौत्र परशुराम जी को प्रदान किया। ब्रह्मर्षि कश्यप तथा महर्षि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त कर भगवान परशुराम समस्त शस्त्र एवं शास्त्रों के ज्ञाता हुए। परशुराम जी सदैव अपने गुरुजनों तथा माता-पिता की आज्ञा का पालन करते थे। भगवान परशुराम जी ने पितृभक्ति के फलस्वरूप अष्ट-चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त किया। इनके तपोबल एवं योग-बल से समस्त भू-मंडल तथा तीनों लोक परिचित थे। भगवान परशुराम जी इतने न्यायप्रिय थे कि उनके आगमन से ही समस्त प्रजा निर्भय हो जाती थी। वह सामाजिक समानता, मानव कल्याण के प्रबल पक्षधर थे।

जब-जब आततायियों ने तप के द्वारा प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल अधर्मपूर्वक किया, जिससे समस्त मानव जाति उनकी अनीतियों, अन्याय एवं अत्याचारों से दुखी हुई, तब-तब भगवान ने धर्मपूर्वक उन अधर्मियों का नाश किया तथा शाश्वत मानवीय धर्म की स्थापना की। इसलिए भगवान परशुराम जी ने सदैव यह प्रयास किया कि इस शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञान को सुपात्र को प्रदान किया जाए ताकि धर्म की अभिवृद्धि हो परन्तु जिस प्रकार विश्वासघात से कर्ण ने भगवान परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त कर अधर्म के कार्य में दुर्योधन का साथ दिया, इससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान प्रदान करने के जो मापदंड परशुराम जी ने स्थापित किए, वे कितने प्रमाणिक थे। शस्त्र एवं शास्त्र ज्ञान का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए ही हो, ऐसी व्यवस्था भगवान परशुराम जी ने की। अधर्म के प्रति सदैव क्रोध परायण रहने वाले भगवान परशुराम जी ने अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दी और उनके आदेशानुसार स्वयं महेन्द्र पर्वत पर चले गए।

एक समय भगवान परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश गए। वहां पार्वतीनंदन गणेश जी ने मार्ग में ही रोक लिया। दोनों में युद्ध हुआ जिससे भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया जिससे वे एकदंत कहलाए। भगवान परशुराम जी ने वैदिक सनातन संस्कृति रक्षार्थ हर युग में अपनी सार्थकता सिद्ध की। त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मिथिलापुरी पहुंच कर अपने संशय के निवारण उपरांत उन्हें वैष्णव धनुष प्रदान किया तथा उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम पधार कर वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे साक्षात परब्रह्म श्रीकृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। कलियुग में होने वाले भगवान के दसवें कल्कि अवतार में भी भगवान कल्कि को भगवान परशुराम जी द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाएगी। परशुराम जी के निर्देशानुसार भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या कर उनसे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करेंगे।

जिनके आगे सम्पूर्ण वेद, उपवेद एवं उपनिषद् गान करते हैं, पीठ पर वाणों से भरा तुणीर तथा कंधे पर दिव्य धनुष तथा हाथ में परशु शोभित हो रहा है, जो यज्ञादि पुण्य कर्मों की सम्पन्नता हेतु कमंडल रखते हैं, समग्र शास्त्रों के मर्मज्ञ भगवान परशुराम जी का अवतरण भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए हुआ। धर्म से द्वेष करने वाले अन्यायियों का दमन करने के लिए तथा जगत की रक्षा के लिए भगवान परशुराम जी ने परशु को धारण किया।

ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदंड धारिणे।
नमस्ते रुद्ररुपाय विष्णवे वेदमूर्तये।।

हाथ में परशु धारण करने वाले भगवान परशुराम जी को नमस्कार। हाथ में धनुष धारण करने वाले परशुराम जी को नमस्कार। रुद्ररूप परशुराम जी को नमस्कार। साक्षात वेदमूर्ति भगवान विष्णुरूप परशुराम जी को नमस्कार। जमदग्निनंदन श्री परशुराम ने ब्राह्मण कुल का मान बढ़ाया। भृगुकुल शिरोमणि रेणुका नंदन भगवान परशुराम जी की यशोकीर्ति का गान तीनों लोकों के प्राणी करते हैं।

शुभ्रदेहं सदा क्रोधरक्तेक्षणम्, भक्तपालं कृपालुं कृपावारिधिम्।
विप्रवंशावतंसं धनुर्धारिणम्, भव्ययज्ञोपवीत कलाकारिणम्।

यस्य हस्ते कुठारं महातीक्ष्णकम् रेणुकानंदन जामदग्न्यं भजे

भगवान परशुराम जी की क्षमाशीलता, दानशीलता, नैतिकता, न्यायप्रियता, मातृ-पितृ भक्ति, समस्त मानवीय समाज के लिए अनुकरणीय एवं वंदनीय है।

-रविशंकर शर्मा
(अध्यक्ष) श्री गीता जयंती महोत्सव कमेटी जालन्धर।

अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह 26 अप्रैल को मनाई जा रही है...इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचाग देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन वास्तु के कुछ उपाय भी किए जाते हैं। इन उपाय को करने से घर में हमेशा बरकत आती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन करने वाले कुछ वास्तु के उपाय

1. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अक्षय तृतीया के दिन आप घर या फिर दुकान में धन रखने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा को चुनें। इस दिशा में धन रखने से आर्थिक तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी।
2. अक्षय तृतीया के दिन आप घर या फिर कार्यक्षेत्र में अच्छे से देख लें कि मकड़ी के जाले ना हों। वास्तु के अनुसार, मकड़ी के जाल धन आने का रास्ता रोक देते हैं इसलिए सफाई करते रहें।
3. अक्षय तृतीया के दिन घर में थोड़ा परिवर्तन करें। आप इस दिन उत्तर दिशा में दर्पण लगाएं। इस दिशा में दर्पण लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ती है। जिससे आय और धन में वृद्धि होती है।
4. अगर आपके घर में कोई नल टपक रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन सही करा लें। वास्तु के अनुसार, नल से पैसा टपकने का मतलब है कि आपका पैसा भी इसी तरह बह रहा है। इसलिए अपने घर के सभी नलों को सही करा लें। पानी का घर में लगातार बहना अशुभ माना जाता है।
5. अक्षय तृतीया के दिन आप घर में फिश पॉट जरूर रखें। इस फिश पॉट में आठ गोल्डन फिश के साथ एक काले रंग की मछली रखें। ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होती है। फिश पॉट को घर में ड्राइंग रूम के दाएं हाथ पर रखें। आपके सभी बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे।
6. अक्षय तृतीया के दिनआप जिस चीज का बिजनेस या फिर जिस प्रकार की नौकरी करते हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें घर पर लगाएं। इससे आपके व्यापार धंधे में वद्धि होती है और नौकरी में प्रमोशन भी मिलता है। जो व्यापार आप करते हैं उसी से जुड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र सही दिशा में उपयुक्त स्थान पर लगा सकते हैं।
7. इस दिन मिट्टी की मटकी पर खरबूज रख कर किसी सुहागन को दान कर सकते हैं और उनसे एक रुपए का सिक्का लेकर गल्ले में रखें। यह मनचाहे धन के लिए सटीक उपाय है...

फेसबुक ने जियो प्लेटफार्म्स में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी, 43574 करोड़ रुपये में हुआ सौदा

नयी दिल्ली। फेसबुक ने मुकेश अंबानी के नेतृव वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की कंपनी जियो प्लेटफार्म्स लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.7 अरब डॉलर या करीब 43,574 करोड़ रुपये निवेश का करार किया है। यह भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) है। इस सौदे से आरआईएल को कर्ज कम करने में मदद मिलेगी और समूह अमेजन तथा वॉलमार्ट के मुकाबले भारतीय ई-कॉमर्स मंच बनाने में व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरी ओर फेसबुक की भारत में स्थिति और मजबूत होगी।

रिलायंस के बुधवार को एक बयान में कहा, "आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफार्म्स लिमिटेड में 5.7 अरब अमेरिकी डॉलर या 43,574 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा कर रहे हैं, जिससे फेसबुक इसका सबसे बड़ा अल्पांश शेयरधारक बन जाएगा।" रिलायंस ने कहा कि जियो प्लेटफार्म्स की कीमत 4.62 लाख करोड़ रुपये (70 रुपये प्रति डॉलर की विनिमय दर प 65.95 अरब अमेरिकी डॉलर) आंकी गई है। फेसबुक को नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और उसे जियो प्लेटफार्म्स के बोर्ड में जगह मिलेगी। इस कंपनी के बोर्ड में मुकेश अंबानी की बेटी और बेटा ईशा और आकाश भी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरसंचार नेटवर्क जियो की शत प्रतिशत हिस्सेदारी जियो प्लेटफार्म्स लिमिटेड के पास है।

बयान में कहा गया है कि जियो प्लेटफार्म्स में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99 प्रतिशत होगी। जियो प्लेटफार्म्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। इसके ग्राहकों की संख्या 38.8 करोड़ से अधिक है। इस सौदे के लिए सलाहकारों ने पिछले साल नवंबर में मसौदा बनाना शुरू किया था, और जुलाई या अगस्त में दोनों समूहों के बीच वाणिज्यिक वार्ता शुरू हुई। यह सौदा पहले 31 मार्च को होना था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बातचीत में देरी हुई। आरआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ साझेदारी पर कहा, "जब रिलायंस ने 2016 में जियो की पेशकश की थी, तब हम भारत के डिजिटल सर्वोदय के सपने से प्रेरित थे- भारत का ऐसा समावेशी डिजिटल उत्कर्ष, जिससे प्रत्येक भारतीय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और भारत दुनिया का अग्रणी डिजिटल समाज बने।" उन्होंने कहा कि जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से 'डिजिटल इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि कोरोना वायरस संकट टल जाने के बाद बहुत जल्द भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

अंबानी ने पिछले साल अगस्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को कुछ कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के बारे में बताया था, ताकि 2021 तक समूह को कर्ज मुक्त किया जा सके। आरआईएल द्वारा अपने कर्ज को कम करने के प्रयासों के तहत फेसबुक के साथ यह सौदा किया गया है। आरआईएल अपने कई व्यवसायों में रणनीतिक भागीदारी की तलाश कर रही है। समूह अपने तेल-रसायन कारोबार में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए सऊदी अरामको के साथ बातचीत भी कर रहा है। समूह ने अगले साल तक कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य तय किया है। जियो में हिस्सेदारी के लिए कथित तौर पर गूगल से भी बातचीत की जा रही थी, लेकिन उन बातचीत के नतीजे के बारे में जानकारी फिलहाल नहीं है। ताजा सौदा जियो और फेसबुक दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद यह किसी कंपनी में हिस्सेदारी उसके लिए सबसे बड़ा सौदा है।

आरआईएल ने कहा कि इस निवेश के साथ जियो प्लेटफार्म्स, रिलायंस रिटेल लिमिटेड और व्हाट्सएप के बीच भी एक वाणिज्यिक साझेदारी समझौता हुआ है। इसके तहत व्हाट्सएप के इस्तेमाल से जियोमार्ट प्लेटफार्म पर रिलायंस रिटेल के नए वाणिज्यिक कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और व्हाट्सऐप पर छोटे कारोबारियों को सहायता दी जाएगी। जियोमार्ट पारंपरिक दुकानदारों और किराना स्टोर की ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है। आरआईएल ने कहा कि इस सौदे के लिए अभी नियामक और अन्य मंजूरियां मिलनी बाकी हैं। सौदे के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी लेनी होगी। इस सौदे के लिए मॉर्गन स्टेनली ने एक वित्तीय सलाहकार के रूप में और एजेडबी एंड पार्टनर्स और डेविस पोल्क एंड वार्डवेल ने कानूनी सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दीं। आरआईएल ने जियो पर करीब 50 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जिनमें से ज्यादातर धन उधार लिया गया था। जियो ने 2016 में मुफ्त कॉल और सस्ते डेटा के साथ भारतीय बाजार में कारोबार की शुरुआत की। आरआईएल पर दिसंबर तिमाही के अंत में 3,06,851 करोड़ रुपये का कर्ज था। उसके पास 1,53,719 करोड़ रुपये की आरक्षित नकदी भी थी और इस तरह उस पर शुद्ध कर्ज 1,53,132 करोड़ रुपये था।

कीटाणुनाशक रसायानों का मानव शरीर पर पर सीधा प्रयोग हो सकता है नुकसानदेह : एएमएआई

नयी दिल्ली। छार बनाने वाली कंपनियों के संगठन एएमएआई ने कीटाणुनाशक रसायनों को सीधे मानव शरीर पर उपयोग किये जाने को लेकर आगाह किया है और कहा है कि इससे नुकसान हो सकता है। एएमएआई (अलकली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) अलकली उद्योग का प्रतिनिधि निकाय हैं। इस क्षेत्र की कंपनियां सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोरीन, ब्लीचिंग सोल्यूश/पाउडर जैसे रसायन बनाती है। इन रसायनों का काम कीटाणुओं को समाप्त करना है। उद्योग संगठन ने मंगलवार को कहा कि मीडिया में कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकने के लिये सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन और हाइड्रोजन परआक्साइड जैसे रसायानों के मानव शरीर पर उपयोग की रिपोर्ट है। एएमएआई ने एक बयान में कहा, "सोडियम हाइपोक्लोराइट एक मजबूत कीटाणुनाशक है। इसका उपयग घोल के रूप में फर्श और वस्तुओं को संक्रण मुक्त करने के लिये किया जाता है। मानव शरीर के इसके संपर्क में आने पर खुजलाहट, जलन और त्वचा की समस्या हो सकती है।" इसी प्रकार, हाइड्रोजन परआक्साइड मजबूत ब्लीचिंग (किसी वस्तु को चमकाने में उपयोग होने वाला) एजेंट हैं। इसका वस्तुओं और फर्श पर उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। संगठन ने कहा, "इन रसायनों का चेहरे पर उपयोग और खतरनाक हो सकता है...इससे मानव शरीर पर उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।" एएमएआई ने कहा कि विशेष प्रकार के चैंबर भी बनाने की रिपोर्ट है जिसका उपयोग वहां से लोगों को गुजारकर रसायनों के छिड़काव के जरिये उन्हें कीटाणु मुक्त बनाने में किया जा रहा है। उद्योग संगठन के अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल ने कहा, "हम सरकार और स्थानीय निकायों से इन कीटाणुनाशक के सुरक्षित उपयोग को लेकर संपर्क कर रहे हैं।" संगठन के अनुसार अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर हाथों को साफ रखने के लिये उपयोग करना चाहिए। शरीर के किसी भी अन्य हिस्से को केवल साबुन और पानी से ही साफ करना चाहिए।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दस सड़क परियोजनाओं पर टोल वसूली शुरू की

नयी दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने मंगलवार को कहा कि उसने अपनी 10 सड़क परियोजनाओं पर पथ कर (टोल) वसूली का कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये सभी एहतियाती इंतजाम किए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू पाबंदियों को धीरे धरे उठाने के सरकार के निर्णय के अनुसार कंपनी ने 20 अप्रैल की मध्य रात्रि से अपनी सड़क परियोजनाओं पर पथ कर का काम शुरू कर दिया है। बयान के अनुसार, "अपने कर्मचरियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डिविजन ने सभी एहतियाती इंजाम किए हैं।" आर इंफ्रा अपनी विशेष उद्देश्यीय कंपनिया के जरिये 10 सड़क परियोजनाओं का परिचालन कर रही है। ये परियोजनाएं बनाओ, चलाओ और सौंप दो (बीओटी) आधार पर कंपनी को दी गयी हैं।

Mahindra KUV100 NXT का बीएस6 मॉडल लॉन्च, कीमत 5.54 लाख से शुरू

नई दिल्ली। Mahindra ने अपनी छोटी एसयूवी KVU100 NXT का बीएस6 कम्प्लायंट मॉडल लॉन्च कर दिया। 2020 Mahindra KUV100 NXT BS6 की शुरुआती कीमत 5.54 लाख रुपये है। इसे चार वेरियंट (K2+, K4+, K6+ और K8) में बाजार में उतारा गया है। इनमें बेस वेरियंट K2+ सिर्फ 6-सीटर, जबकि अन्य तीनों वेरियंट 6-सीटर और 5-सीटर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। महिंद्रा KVU100 NXT में अब बीएस6 कम्प्लायंट 1.2-लीटर, 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 5500rpm पर 82bhp का पावर और 3500-3600rpm पर 115Nm टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। दूसरी ओर, कंपनी ने KVU100 NXT का डीजल मॉडल बंद कर दिया, जो 1.2-लीटर डीजल इंजन के साथ आता था।

कई कलर ऑप्शन

बीएस6 केयूवी100 एनएक्सटी 8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इनमें डिजाइनर ग्रे, रेड, मिडनाइट ब्लैक, डैजलिंग सिल्वर, फेयरी ऑरेंज और पर्ल वाइट शामिल हैं। इनके अलावा दो ड्यूल-टोन पेंट ऑप्शन- सिल्वर-ब्लैक और रेड-ब्लैक भी उपलब्ध हैं। महिंद्रा की इस छोटी एसयूवी में 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और फोन कॉल कंट्रोल, हाइट अजस्टेबल ड्राइवर सीट और 6-सीटर वेरियंट में फ्रंट-रो आर्मरेस्ट जैसे फीचर मिलते हैं। सेफ्टी के लिए एबीएस, ईबीडी, ड्यूल-एयरबैग्स और रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर स्टैंडर्ड, यानी बेस वेरियंट से दिए गए हैं। बता दें कि KVU100 NXT महिंद्रा की भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे छोटी और सबसे सस्ती एसयूवी है। यह अपने सेगमेंट की एकमात्र एसयूवी है, जो 6-सीटर ऑप्शन में आती है।

Coronavirus

बीच वाली सीट खाली नहीं रखेंगी एयरलाइन्स

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के चलते हर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है। यही वजह है कि लॉकडाउन भी लागू किया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो सके और कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। इसी बीच एक सवाल ये उठ रहा था कि आखिर अब रेल, बस और हवाई सेवाएं कब से चलेंगी। रेल और बस का तो अभी भी पता नहीं, लेकिन हवाई यात्रा के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि बीच की सीट खाली रख कर हवाई सेवाएं दोबारा शुरू की जा सकती हैं, लेकिन एयरलाइन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

प्रस्ताव ठुकराने के साथ-साथ सुझाया उपाय

प्रस्ताव ठुकराया और दूसरा सुझाव दिया

एयरलाइन ने फ्लाइट्स में बीच की सीट खाली रखने के प्रस्ताव को ठुकराया जरूर है, लेकिन उससे बेहतर उपाय सुझाया है। एरलाइन्स के प्रमोटर्स ने सरकार के इस प्रस्ताव को सही नहीं बताते हुए कहा है कि इस तरह से यात्रियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो इससे एयरलाइन्स की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाएगी, जो पहले से ही कोरोना महामारी की वजह से बेहद खराब है। प्रस्ताव ठुकराने के साथ-साथ एयरलाइन्स ने सुझाव दिया है कि सूट, ग्लव्स और मास्क जैसे पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये न सिर्फ यात्रियों, बल्कि क्रू मेंबर्स के लिए भी जरूरी होने चाहिए। स्पाइसजेट के चेरमैन अजय सिंह ने कहा कि बीच की सीट खाली रखने भर से दो लोगों के बीच में जरूरी दूरी नहीं रखी जा सकती है, जिससे वह सुरक्षित रहें, बल्कि मास्क और ग्लव्स के जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

2 मीटर की दूरी नहीं रखी जा सकती

हाल ही में डीजीसीए ने तय किया था कि जब एयरलाइन सेवाएं शुरू होंगी तो फ्लाइट में बीच वाली सीट खाली रखी जाएगी। हालांकि, एयरलाइन्स ने तर्क दिया है कि इससे 2 मीटर की दूरी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, जो कि स्वास्थ्य एजेंसियों ने सुझाया है।

एक उदाहरण के तौर पर देखें तो सामान्य इंडिगो ए320 18 इंच की सीट है और 25 इंच का गलियारा है। ऐसे में अगर 2 मीटर की दूरी रखनी है तो पूरी लाइन में दो विंडो सीट पर दो यात्री ही बैठ सकते हैं। 6 सीटों की लाइन में बाकी की 4 सीटें खाली रखनी होंगी। 2 मीटर का मतलब एयरलाइन को हर दूसरी विंडो सीट खाली छोड़नी होगी। इंडिगो के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि किराया तीन गुना ना बढ़ा दिया जाए, जिसके लिए ग्राहक कभी तैयार नहीं होंगे।

खपत बढ़ने के बावजूद 35 फीसदी तक सस्ते हुए दूग्ध उत्पाद

मक्खन, घी, पनीर और दूध पाउडर की बिक्री बढ़ी

नई दिल्ली। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पाद बनाने वाली सहकारी संस्था, जीसीएमएमएफ को कोविड-19 वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से आई आर्थिक नरमी के बावजूद चालू वित्तवर्ष में अपने कारोबार के 15 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। समाप्त वित्त वर्ष 2019-20 में संस्था ने 38,550 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक आर.एस. सोढी ने कहा कि मक्खन, घी, पनीर और दूध पाउडर की बिक्री में 20 से 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि लोग अधिक खपत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, किसानों से दूध की खरीद में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि असंगठित क्षेत्र के द्वारा खरीद नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिशेष दूध को स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) के निर्माण के लिए संसाधित किया जा रहा है, जिसकी कीमत लॉकडाउन से पहले 320 रुपये से 250 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। सोढ़ी ने कहा कि घरों में दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की होने वाली खपत बढ़ने की उम्मीद है। इससे लॉकडाऊन के दौरान होटल, रेस्तरां और कैफेटेरिया के बंद होने की वजह से बिक्री में जो कमी आई है उसकी भरपाई भी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का खाद्य उत्पादों की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस महीने मूल्य के संदर्भ में हमारी बिक्री पिछले साल के इसी महीने के बराबर ही है। कुछ उत्पादों की मांग में कमी आई है लेकिन कई उत्पादों की बिक्री बढ़ गई है। वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान जीसीएमएमएफ का कारोबार 17 प्रतिशत बढ़कर 38,550 करोड़ रुपये का हो गया।

आइसक्रीम की मांग में 85 प्रतिशत की कमी

दूध कारोबार की मौजूदा स्थिति के बारे में सोढ़ी ने कहा, धीरे-धीरे चीजें सामान्य होने लगी हैं। बिक्री के बारे में, उन्होंने कहा कि ताजा दूध की मांग में आठ प्रतिशत तक की गिरावट आई है क्योंकि होटल और रेस्तरां बंद हैं। होटल, रेस्तरां और कैफेटेरिया खंड में कुल मांग का 12-15 प्रतिशत का योगदान है, लेकिन, ताजा दूध और मक्खन दूध की घरेलू खपत में वृद्धि के कारण गिरावट का स्तर कम है। हालांकि, उन्होंने बताया कि आइसक्रीम की मांग में 85 प्रतिशत की तेज गिरावट आई है, जबकि क्रीम और मोजेरेला चीज़ की बिक्री में क्रमशः 70 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की गिरावट है।

लॉकडाऊन के कारण स्वर्ण आभूषण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभावः इक्रा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

साख निर्धारण एजेंसी इक्रा के अनुसार, कोरोनोवायरस (कोविड-19) के प्रकोप और अक्षय तृतीया से पहले 'लॉकडाउन' के कारण उद्योग पर असर होगा और यह स्थिति स्वर्ण आभूषण खुदरा उद्योग की वित्तीय साख के लिहाज से प्रतिकूल रहेगी। अक्षय तृतीया के दौरान सोने के आभूषणों को खरीदना शुभ माना जाता है, जो पर्व इस साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में पड़ रहा है। इक्रा ने एक रिपोर्ट में कहा, पिछले दो वर्षों में, घरेलू स्वर्ण आभूषणों का खुदरा कारोबार,- आर्थिक

सुस्ती के बीच कमजोर उपभोक्ता मांग, सोने की कीमतों में वृद्धि और ग्रामीण उत्पादन कम रहने, नियामकीय नीतिगत हस्तक्षेप और बैंकों द्वारा ऋण देने में सतर्कता बरतना जैसे कारणों से प्रभावित हुआ है। इक्रा ने कहा, 'इस पृष्ठभूमि में, अक्षय तृतीया के ऐन मौके के पहले कोविड-19 के व्यापक प्रकोप और लॉकडाउन की घोषणा, अल्पावधि में स्वर्ण आभूषण खुदरा उद्योग के वित्तीय साख के लिहाज से प्रतिकूल साबित होगी।' लॉकडाउन के परिणामस्वरूप देश भर में खुदरा स्टोर बंद हैं। इक्रा ने कहा कि इसके अलावा गैर जरूरी सामानों की आवाजाही पर प्रतिबंध के साथ आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है। इक्रा के उपाध्यक्ष के श्रीकुमार ने कहा, 'चूंकि खुदरा दुकानें बंद हैं और सोने की गिनती गैर- जरूरी सामान में होती है इसलिए मांग में धीरे-धीरे सुधार आने की संभावना है, इसलिए अगले कुछ महीनों तक आभूषण विक्रेता के पास ग्राहकों की संख्या कम रह सकती है। विशेष रूप से, अप्रैल 2020 के अंतिम सप्ताह में पड़ने वाले अक्षय तृतीया के दौरान बिक्री प्रभावित हो सकती है।''

ट्रक आपरेटरों की मांग, ईंधन के दाम घटाए, टोल संग्रह स्थगित करे सरकार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट के बाद ट्रक आपरेटरों के संगठन आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने सरकार से ईंधन कीमतों में कटौती की मांग की है। एआईएमटीसी ने इसके साथ ही टोल संग्रह भी स्थगित करने की मांग की है। ट्रक आपरेटरों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजमार्गों पर टोल संग्रह को तत्काल स्थगित किया जाए। एआईएमटीसी का कहना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद से ट्रांसपोर्ट क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, ऐसे में उसे राहत की दरकार है। एआईएमटीसी ट्रांसपोर्टरों का संगठन है। इसके सदस्यों में 95 लाख ट्रक आपरेटरों और इकाइयों शामिल हैं। एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा, ''डीजल और पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी से हमारी स्थिति और खराब हुई है। ईंधन कीमतों में कटौती नहीं की जा रही। इन पर कर और मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरें बढ़ा दी गई हैं।'' उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है। 17 अप्रैल, 2020 को भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की लागत 20.56 डॉलर प्रति बैरल थी। यह लागत ओमान, दुबई और ब्रेंट कच्चे तेल का औसत है। अटवाल ने कहा, ''इस साल की शुरुताअ से ब्रेंट तेल के दाम करीब 60 प्रतिशत नीचे आ चुके हैं। वहीं इस दौरान डीजल के दाम सिर्फ 10 प्रतिशत घटे हैं।'' आईएमटीसी ने कहा कि मई, 2014 से सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया है। इसके उलट उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) का मुनाफा बढ़ाने का काम किया है। अटवाल ने कहा कि कच्चे तेल कीमतों में वैट और उत्पाद शुल्क से भी ईंधन का दाम तय होता है। हम एक नवंबर, 2014 को पेट्रोल पर 9.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3.46 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क दे रहे थे। ''आज पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 22.98 रुपये प्रति लीटर (सड़क उपकर सहित) और डीजल पर 18.83 रुपये प्रति लीटर हो गया है।'' उन्होंने कहा कि दिल्ली में पेट्रोल की खरीद पर हम प्रति लीटर 37.84 रुपये और डीजल पर 28.01 रुपये प्रति लीटर का कर देते हैं।

चांदी वायदा भाव 546 रुपये की गिरावट के साथ 41,202 रुपये प्रति किग्रा

नयी दिल्ली। हाजिर बाजार की कमजोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदे की कटान की जिससे बुधवार को चांदी का वायदा भाव 546 रुपये की गिरावट के साथ 41,202 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मई डिलिवरी के लिए चांदी का भाव 546 रुपये यानी 1.31 प्रतिशत घटकर 41,202 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसमें 3,224 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार जुलाई डिलिवरी के लिए चांदी 352 रुपये यानी 0.83 प्रतिशत घटकर 42,080 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इसमें 1,729 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कमजोर हाजिर मांग के कारण मुख्यतः यहां चांदी वायदा कीमतों पर दबाव रहा।हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.79 प्रतिशत की तेजी दर्शाती 15.11 डॉलर प्रति औंस हो गयी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।